यूपीआई लेनदेन पर नहीं लगेगा कोई शुल्क : आरबीआई

यूपीआई पर ट्रांजैक्शन फीस का डर खत्म, राहत की खबर

यूजर्स के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा- मल्होत्रा

मुंबई, 1 अक्टूबर. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से डिजिटल लेनदेन करने वाले करोड़ों भारतीयों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई लेनदेन पर किसी प्रकार का शुल्क लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.

बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में गवर्नर ने कहा कि देश में डिजिटल इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि आम जनता को सुलभ, सुरक्षित और निन्शुल्क भुगतान विकल्प मिलते रहें. यूपीआई प्रणाली ने ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, और इस पर शुल्क लगाने की बात फिलहाल विचाराधीन भी नहीं है. गवर्नर से जब स्मार्टफोन लोन पर डिफॉल्ट करने की स्थिति में डिवाइस लॉक करने के अधिकार पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह विचार परीक्षण स्तर पर है. इसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि ग्राहक के अधिकार और गोपनीयता दोनों की रक्षा हो. इसके अलावा, आरबीआई डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए एक विशेष सॉ टवेयर तैयार कर रहा है, जो लेनदेन के समय ही उपयोगकर्ता को अलर्ट देगा कि यह लेनदेन सुरक्षित है या नहीं. इससे धोखेबाजों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने यूपीआई पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने से इनकार किया है. यह फैसला छोटे दुकानदारों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक सभी के लिए राहत लेकर आया है.

> गवर्नर ने तकनीक-सहयोगी सुरक्षा उपायों का भी खुलासा किया. मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद एक संवाददाता स मेलन में इस संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा कि फिलहाल यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव आरबीआई की ओर से नहीं है. लोन पर स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसकी किस्त न भर पाने की स्थिति में बैंक को फोन लॉक करने का अधिकार देने के बारे में पूछे जाने पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह अभी परीक्षणाधीन है. इसमें यह देखा जा रहा है कि ग्राहकों के अधिकारों की भी रक्षा हो.

भारत के जॉब मार्केट में दस प्रतिशत वृद्धि : रिपोर्ट

फ्रेशर्स से अनुभवी पेशेवरों तक भर्तियों में आई तेजी

नौकरी पोर्टल रिपोर्ट के अनुसार भर्तियों में दोहरी अंक वृद्धि

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर. भारत के जॉब मार्केट में सितंबर में सालाना आधार पर दोहरे अंक में वृद्धि हुई है, जिसमें फ्रेशर्स के साथ अनुभवी पेशेवरों की भर्तियां शामिल हैं. यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई.जॉब पोर्टल नौकरी की रिपोर्ट से पता चला है कि फ्रेशर्स की भर्ती में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि 16 वर्ष से अधिक अनुभव वाले पेशेवरों की मांग सालाना आधार पर 13 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है.

महानगरों में भर्तियों को मुख्य रूप से हैदराबाद ने लीड किया, जहां सालाना आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद पुणे का स्थान रहा, जहां 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई.

बीपीओ/आईटीईएस सेक्टर में दोहरे अंकों में भर्तियों में वृद्धि

रिपोर्ट के मुताबिक, सभी श्रेणियों में उच्च वेतन वाली भूमिकाओं की मांग देखी गई. सितंबर में 20 लाख रुपए प्रति वर्ष वेतन वाली भूमिकाओं में सालाना आधार पर 23 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. फ्रैशर्स की मांग में 41 प्रतिशत और मध्य स्तर की भूमिकाओं में 27 प्रतिशत और सीनियर (16 वर्ष से अधिक) भूमिकाओं में 19 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई है.रिपोर्ट के मुताबिक उभरती हुई टेक्नोलॉजी की भूमिकाओं में सालाना आधार पर 85 प्रतिशत और एआई एवं एमएल से जुड़ी नौकरियों में सालाना आधार पर 61 प्रतिशत की बढ़त हुई है.उभरते शहरों में बीपीओ/आईटीईएस सेक्टर में दोहरे अंकों में भर्तियों में वृद्धि देखी गई, जिसमें अहमदाबाद 82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सबसे आगे रहा, उसके बाद जयपुर (50 प्रतिशत) और बड़ौदा (19 प्रतिशत) का स्थान रहा.

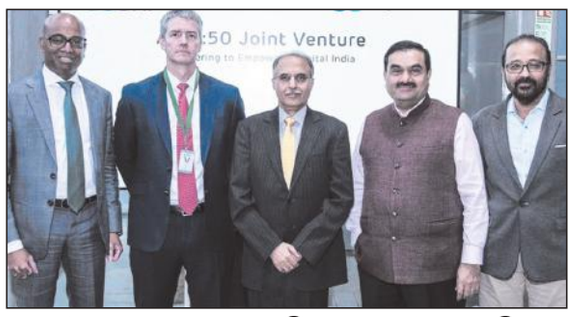

गौतम अडानी पहुंचे नवी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर

- यह सिर्फ हवाई अड्डा नहीं, भारत की भावना है : अडानी
- नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले अंतिम समीक्षा
- गौतम अडानी ने मजदूरों और इंजीनियरों से की बातचीत

मुंबई, 1 अक्टूबर. देश का अगला मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट – नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा – अब उद्घाटन के अंतिम चरण में है. जब दुनिया इस आधुनिक हवाई अड्डे की प्रतीक्षा कर रही है, वहीं इसके निर्माणकर्ता अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने खुद पहुंचकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया और इसे भारत के सामूहिक प्रयास का प्रतीक बताया.

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जल्द ही भारत के सबसे अत्याधुनिक और व्यस्ततम हवाई अड्डों में शामिल होने जा रहा है, अपने उद्घाटन से ठीक पहले पूरी तरह से तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आठ अक्टूबर को इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे. इससे पहले अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के प्रमोटर और अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बुधवार को हवाई अड्डे का गहन निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अडानी ने निर्माण कार्यों की तकनीकी प्रगति, संचालनात्मक सुविधाओं और अंतिम चरण की तैयारियों का जायजा लिया.

यह एयरपोर्ट देश के नवाचार के युग की शुरुआत

उन्होंने कहा, नवी मुंबई एयरपोर्ट केवल एक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह भारत की भावना और हजारों लोगों की मेहनत का जीवंत प्रतीक है. यह एयरपोर्ट भारत के लिए भारत द्वारा बनाया गया है. यह हवाई अड्डा सालाना 9 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला होगा, जो कि देश के आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क और मुंबई के मौजूदा हवाई यातायात पर दबाव कम करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम होगा. अडानी ने कहा, हर रनवे, हर गेट और हर टर्मिनल उन लाखों सपनों से जुड़ा है, जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उड़ान भर रहे हैं. यह एयरपोर्ट देश के आत्मनिर्भरता और नवाचार के युग की शुरुआत है.

कर्मियों के लिए नि :शुल्क न्यूरोथेरेपी-पंचकर्म कैंप शुरू

प्रियदर्शिनी क्लब इंदिरा विहार कॉलोनी में कैंप आयोजित

कर्मचारियों व परिवारजनों को नि :शुल्क पारंपरिक उपचार उपलब्ध

बिलासपुर, 1 अक्टूबर. एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) ने %स्वच्छता ही सेवा - स्वच्छोत्सव 2̀25% अभियान के तहत अपनी ऐतिहासिक सामाजिक पहल को आगे बढ़ाते हुए प्रियदर्शिनी क्लब, इंदिरा विहार कॉलोनी में नि:शुल्क आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी एवं पंचकर्म कैम्प का शुभारंभ किया.

कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने 26 सितंबर को इस चिकित्सा कैंप का उद्घाटन किया. यह पहल सीएमडी हरीश दुहन के दिशा-निर्देशों पर आयोजित की गई है.

आधुनिक जीवनशैली के लिए प्रभावी उपचार- अपने संबोधन में मुख्य अतिथि बिरंची दास ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों से बचाव के लिए हमारी पुरातन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियाँ अत्यंत प्रभावी हैं. उन्होंने कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस नि:शुल्क सुविधा का लाभ उठाने का आह्वान किया.

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर- न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ डॉ. महेंद्र रघुवंशी ने बताया कि इस कैंप के माध्यम से प्रतिभागियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधार, शरीर से विषैले तत्वों की शुद्धि, दर्द निवारण तथा जीवनशैली संबंधी रोगों की रोकथाम के उपाय प्रदान किए जाएंगे.

जीएसटी संग्रह ने बनाया नया रिकॉर्ड

सालाना 9 .1 की वृद्धि, शुद्ध संग्रह भी बढ़ा

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर. देश में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के तहत राजस्व संग्रह सितंबर 2̀25 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस माह कुल सकल जीएसटी संग्रह 1,89`,17 करोड़ रहा, जो सितंबर 2̀24 के मुकाबले 9.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था की कर वसूली प्रणाली ने सितंबर 2025 में मजबूती दिखाई है. जीएसटी संग्रह में लगातार हो रही बढ़ोतरी न केवल आर्थिक गतिविधियों की मजबूती का संकेत है, बल्कि सरकार की बेहतर कर प्रशासन प्रणाली का भी प्रमाण है. इस बार सितंबर में जीएसटी संग्रह 1.89 लाख करोड़ को पार कर गया है, जो पिछले साल की तुलना में 9.1 अधिक है. पिछले वर्ष सितंबर में यह आंकड़ा 1,7×,240 करोड़ था. इस बढ़ोतरी को सरकार ने आर्थिक गतिविधियों की मजबूती और बेहतर अनुपालन प्रणाली का नतीजा बताया है.

इस दौरान कुल जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. सितंबर में कुल ?28,657 करोड़ का रिफंड जारी किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40.1 प्रतिशत अधिक है.

नेपाल-भूटान-श्रीलंका को रु . में कर्ज

भारतीय रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला

मुंबई, 1 अक्टूबर. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका के नागरिकों व बैंकों को भारतीय रुपये में ऋण दिया जा सकेगा. यह कदम भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपये में करने के प्रयासों को और मजबूती देगा.

बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने संवाददाताओं को बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना और रुपये को एक स्थिर व विश्वसनीय मुद्रा के रूप में स्थापित करना है. इस घोषणा के अनुसार, भारत के अधिकृत डीलर बैंक अब इन तीन देशों के नागरिकों और वहां के बैंकों को भारतीय मुद्रा में ऋण देने में सक्षम होंगे. इस निर्णय से भारत के साथ व्यापार करने वाले पड़ोसी देशों को डॉलर या अन्य विदेशी मुद्रा की निर्भरता से राहत मिलेगी और व्यापार प्रक्रिया सरल होगी. इस फैसले के साथ ही आरबीआई ने विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते में पड़ी अधिशेष राशि को अब सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा कॉर्पोरेट बांड और वाणिज्यिक पत्रों में निवेश करने की भी मंजूरी दी है.

विमान ईंधन 3 प्रतिशत महंगा, हवाई यात्रा हो सकती है खर्चीली

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर. हवाई सफर करने वालों के लिए एक बुरी खबर है. तेल विपणन कंपनियों ने बुधवार से विमान ईंधन्न की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा की लागत बढ़ सकती है. देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में अब्र ज्ञस्न की कीमत 93,766.02 रुपये प्रति किलो लीटर हो गई है, जो कि सितंबर में 90,713.41 रुपये थी. यानी 3,053.61 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है..

रिलायंस डिजिटल का फेस्टिवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू

इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर 25 अक्टूबर तक

मुंबई, 1 अक्टूबर. रिलायंस डिजिटल ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत में फेस्टिवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेल लॉन्च की है, जिसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और नई तकनीक पर आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं.

यह सेल 25 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी, जहां ग्राहक रिलायंस डिजिटल, माय जियो स्टोर्स, जियो मार्ट डिजिटल स्टोर्स और ऑनलाइन वेबसाइट www.reliancedigital.in पर जीएसटी कम कीमतों का फायदा उठा सकते हैं. लीडिंग बैंक कार्ड्स पर 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी उपलब्ध है.

कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि पेपर फाइनेंस विकल्प चुनने पर ग्राहकों को 30,000 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है, जिससे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना आसान हो जाएगा. इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, नई तकनीक और फेस्टिव जश्न के लिए जरूरी उत्पादों पर निवेश का बेहतरीन मौका है.

समाचार विशेष

न्याय का कार्ड खेल रहे राहुल

किंगमेकर ईबीसी पर चली सोची समझी चाल, 2 .7 करोड़ वोटरों पर सीधी नजर

पटना. नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने 2̀23 में जाति आधारित गणना कराकर ईबीसी के लिए अतिरिक्त आठ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक ठहराया. विपक्ष यही से दांव चलने लगा. उसका आरोप है कि अगर सरकार आरक्षण में वृद्धि को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कर देती, तो उसे न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दे पाता. इस क्षोभ के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यह वादा कर रहे कि महागठबंधन के सत्ता में आने पर वे ईबीसी के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करेंगे और उसे संवैधानिक कवच पहनाएंगे.

हालांकि, इसके लिए केंद्र में भी अपनी सरकार चाहिए, जबकि लोकसभा चुनाव 2029 के मध्य में संभावित है. दरअसल, इस वादे के साथ राहुल का फोकस 90 प्रतिशत जनसंख्या (ओबीसी/ ईबीसी/ अनुसूचित जाति/ मुसलमान) पर है, जो नरेन्द्र मोदी के 90 प्रतिशत (मुसलमानों को छोड़कर) के विरुद्ध दिखाने का प्रयास है. उनकी यह रणनीति एक नया जनाधार तैयार कर कांग्रेस को राजद की छाया से बाहर निकालने में भी सहायक हो सकती है.

इंटरनेट मीडिया पर उनके समर्थक पोस्ट इसे ईबीसी एकता बता रहे, लेकिन एनडीए के दृष्टिकोण से यह नकारात्मक राजनीति है. इस दांव-पेच में अगर ईबीसी वोट बंटे, तो महागठबंधन को मजबूती मिलेगी. हालांकि, एनडीए की पकड़ इस प्रयास में बड़ी चुनौती है. जिस ईबीसी को कर्पूरी ठाकुर ने समाज की मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना किया था , उसे नीतीश कुमार ने काफी हद तक साकार किया. पिछले दो दशक के दौरान इस वर्ग को आत्मबल के साथ आर्थिक बल भी मिला है. राजनीतिक पहुंच-पैठ बढ़ी है. अब इस समाज की संप्रभु वर्ग से प्रतिस्पर्द्धा है और बराबर की हैसियत की इच्छा. राजनीति के लिए यहीं से अवसर निकल आता है. ललक और क्षोभ के संयोग से परिवर्तन की संभावना बनती है. इसलिए महागठबंधन ईबीसी पर दोहरे डोरे डाल रहा.

लंबे समय की सरकार से जब जनता में थोड़ा-बहुत असंतोष होता है, तो विपक्ष को ऐसी ही होशियारी की सूझती है. महागठबंधन के लिए तो यह रणनीति इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि अब तक के जनाधार पर वह अधिकतम सीटों तक पहुंच चुकी है. यह उसके रणनीतिकारों का मानना है. राजद-कांग्रेस की अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट भी बता रही कि जनाधार का विस्तार किए बगैर बहुमत के बराबर सीटों का जुगाड़ संभव नहीं.

असंतोष को भुनाने का प्रयास

कांग्रेस का परंपरागत जनाधार (सवर्ण-अनुसूचित जाति-मुसलमान) पहले ही उसके हाथ से खिसक चुका है. उसका एक अंश (मुसलमान) तो अभी राजद से भी गलबहियां है. अनुसूचित जाति के मतदाता परिस्थिति, क्षेत्र और उप-जातियों के हिसाब से कई हिस्सों में बंट जाते हैं, जबकि सवर्ण बहुलता में एनडीए के साथ हो लिए हैं. ऐसे में कांग्रेस नया जनाधार बनाने के लिए तत्पर है. उसके लिए बड़ी जनसंख्या वाला ईबीसी इसलिए भी उपयुक्त है, क्योंकि वहां अभी बेचारगी दूसरे वर्गों की तुलना में अधिक है. इसलिए राहुल और तेजस्वी अति-पिछड़ा न्याय की पैरोकारी कर रहे, लेकिन नीतीश कुमार का पुराना प्रभाव और एनडीए की कल्याणकारी योजनाएं उसे तगड़ी चुनौती दे रही है. बेरोजगारी, पलायन और आरक्षण की मांगों पर ईबीसी के एक हिस्से में असंतोष है. बरहाल महागठबंधन का प्रयास उस असंतोष को प्रबल कर जनसमर्थन जुटाने का है. इसीलिए राहुल न्याय का कार्ड चल रहे. सामाजिक न्याय, रोजगार और वोट सुरक्षा पर केंद्रित उनकी रणनीति इस कार्ड का अंश है. इस वर्ष राहुल बिहार में पांच बार आ चुके हैं.

आर.के. सिंह का भाजपा से मोहभंग!

आरा. पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने अपनी ही पार्टी, बीजेपी, के खिलाफ बगावती तेवर अपना लिए हैं. हाल ही में आरा में आयोजित राजपूत समाज के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर राजपूत समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया.

इस दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वह अपनी नई पार्टी बनाने पर विचार कर रहे हैं. आर.के. सिंह का आरोप है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के बड़े नेताओं ने उनके साथ भीतरघात किया, जिसकी वजह से वह चुनाव हार गए. उन्होंने कहा कि इसी वजह से अब वो राजनीति में एक नए विकल्प की तलाश में हैं.

राजपूतों का प्रतिनिधित्व घटाने का आरोप

आर.के. सिंह ने अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ उदाहरण दिए. उन्होंने कहा कि कैसे कुड़मिया और औरंगाबाद जैसी सीटें हाथ से निकल गईं, क्योंकि पार्टी ने राजपूतों की अनदेखी की. उन्होंने बीजेपी पर राज्य और केंद्र दोनों जगह राजपूतों का प्रतिनिधित्व घटाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा- आज बीजेपी के मंच पर एक भी राजपूत नेता नहीं है. मुझे यह बात कहने में कोई शर्म नहीं है.

केरल में कांग्रेस नेताओं की दावेदारी

थरूर की राजनीति ने उनको कांग्रेस आलाकमान से दूर कर दिया है

तिरुवनंतपुरम. अगले साल अप्रैल में केरल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है. वहां के कांग्रेस नेता इस बात से खुश हैं कि मुख्यमंत्री पद का एक दावेदार कम हो गया. शशि थरूर की राजनीति ने उनको कांग्रेस आलाकमान से दूर कर दिया है और इस तरह वे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से भी दूर हो गए हैं.

उनके दूर होने के बाद भी दावेदारी की संख्या बड़ी लंबी है. प्रदेश के तमाम बड़े नेता, जो कभी सीएम पद के दावेदार रहे हैं वे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको केसी वेणगोपाल का खतरा दिख रहा है. उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो केसीवी ही सीएम होंगे. उनकी हैसियत कांग्रेस के दिग्गज एके एंटनी वाली हो गई है. इसका मतलब है कि या तो वे खुद बन जाएंगे या वही बनेगा, जिसको वे चाहेंगे. जैसे एंटनी वे वायलार रवि की जगह ओमन चांडी को बनवाया था.

> बहरहाल, प्रदेश के पुराने नेताओं में सबसे तगड़ी दावेदारी रमेश चेन्निथला की है. उनके अलावा सुधाकरण और सतीशन की दावेदारी अपनी जगह है. करुणाकरण परिवार के लोग तो अब थक हार कर दावेदारी छोड़ चुके हैं. पिछले कुछ दिनों से चेन्निथला ड्रग्स के खिलाफ यात्रा निकाल कर रहे हैं. वे चाहते थे कि केरल की वायनाड सीट की सांसद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी यात्रा में शामिल हों. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. हालांकि पिछले दिनों प्रियंका वायनाड में थीं.

विशेष | **भाजपा को मिले पांच हजार से ज्यादा टिकट के दावेदार ; पटना से सबसे अधिक आवेदन**

चुनाव लड़ने युवाओं में लगी होड़

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है. निर्वाचन आयोग की तैयारियों और राजनीतिक गतिविधियों को देखकर यह कयास लगाया जा रहा है कि अगले महीने ही चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी.

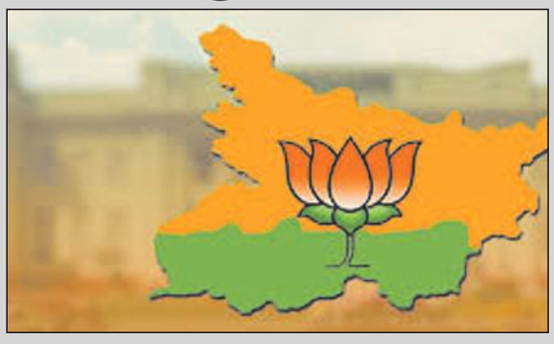

ऐसे में राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं. इसी कड़ी में भाजपा ने भी अंदरूनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी ने दो दिनों की विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें सीट बंटवारे और उम्मीदवार चयन पर चर्चा होगी. लेकिन इससे पहले भाजपा ने अपने सभी जिलों और इलाकों से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले नेताओं का बायोडाटा मांगा था. इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी कार्यालय में बायोडाटा का अंबार लग गया है. जानकारी के मुताबिक, अब तक पांच हजार से ज्यादा लोग भाजपा से टिकट पाने के लिए आवेदन कर चुके हैं. यह सिलसिला लगातार जारी है और हर दिन नए आवेदन पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं.

इन आवेदनों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की है. अधिकांश आवेदक 35 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के हैं. इनमें पार्टी से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता, पूर्व विधायक, ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं.

> **भाजपा नेतृत्व के सामने चुनौती**
>
> राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि कई मौजूदा विधायकों का टिकट इस बार कट सकता है. खासकर ऐसे विधायक जो लंबे समय से सीट पर काबिज हैं और अब उम्रदराज हो चुके हैं. यही वजह है कि नए दावेदार सक्रिय रूप से आगे आकर बायोडाटा जमा कर रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर अपना दावा भी मजबूत कर रहे हैं. कई आवेदक यह तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी की सेवा की है.